

## संपादकीय

### नाम में धड़कता शहर

इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के पीछे की मंथा समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी की सरकारें उन तमाम नामों से छुटकारा चाहती हैं, जिनका संबंध उनकी नजर में किसी न किसी रूप में इस्लाम या मुस्लिम संप्रवाय से है। इसी सोच के तहत कुछ समय पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदला गया। अब इलाहाबाद का नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि यह नाम मुगल सम्राट् अकबर के दिए नाम का एक बदला हुआ रूप है। हालांकि बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं करती। उसकी दलील यह रहती है कि वह शहरों के मूल या प्राचीन नाम को फिर से स्थापित करना चाहती है। लेकिन सचाई यह है कि भारत में कई शहरों के एकाधिक नाम रहे हैं। अलग-अलग कालखंडों में नए नाम आते हैं, साथ में पुराने भी चलते रहते हैं।

लोग इन सबको बर्खाबी जानते हैं और अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से बरतते रहते हैं। बनारस के ही तीन नाम हैं। कुछ लोग उसे बनारस बोलते हैं तो कुछ काशी, जबकि सरकारी कामकाज में वाराणसी का प्रयोग होता है। खुद हमारे देश के कम से कम तीन नाम समान शक्ति से चलते हैं। ऐसा कभी सुना नहीं गया कि एक जगह के कई नाम होने से किसी को कोई दिक्ष त हो रही हो। नाम बदलने के लिए तर्क यह भी दिया जाता है कि विदेशियों के दिए नाम हम क्यों ढोएं? लेकिन जिन शहरों ने साम्राज्यवादी काल के नाम छोड़ दिए, वहां क्या हालात बहुत अच्छे हो गए? क्या कलकत्ता या मद्रास के कोलकाता और चेन्नई हो जाने से लोगों में अपने परिवेश के प्रति अधिक जवाबदेही आ गई? गुडगांव के गुरुग्राम हो जाने से क्या वहां की रातें महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गई? जो नाम हटा दिए जाते हैं, वे जन स्मृतियों से बाहर नहीं जाते। लेकिन एक नाम का हटना सिर्फ एक संबोधन का मिटना नहीं, एक इतिहास का धूंध में जाना होता है। 1575 में संगम के सामरिक महत्व को देखते हुए सम्राट् अकबर ने 'इलाहाबास' के नाम से शहर स्थापित किया। संभव है, इलाहाबास 'दीन-ए-इलाही' से प्रेरित हो, जिसकी बुनियाद 'सुलह कुल' थी। एक ऐसी सोच, जिसके तहत हर धर्म से जुड़े व्यक्ति को वासना और घमंड जैसी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर संयम और शालीनता जैसी अच्छी प्रवृत्तियां अपनाने को कहा जाता था। यानी समावेश और विविधता इस शहर की नींव में है। जो भी इस शहर में रह, उसने खुद के 'इलाहाबादी' होने पर फस्र किया। यह अकबर इलाहाबादी, फिराक, निराला, महादेवी और बच्चन का शहर है। इलाहाबाद का नाम सामने आते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हाईकोर्ट की तरखी उभरती है। समय बीतने के साथ एक नाम बहुत सारी चीजों से अभिन्न रूप से जुड़ता जाता है। इलाहाबादी अमरुद क्या कभी प्रयागराज से पहचाना जाएगा? शहरों के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए।

### स्वाद और सेहत से भरपूर सेब की खीर



कितने लोगों के लिए : 5  
सामग्री -  
सेब- 500 ग्राम (मीडियम साइज के), फुल 1 ग्राम, दूध- 1 लीटर, चीनी-100 ग्राम, काजू- 2 बड़े टीस्पून (बारीक कटा), किशमिश- 2 बड़े टीस्पून, पिस्टाना- 1/2 छोटी टीस्पून, इलायची पाउडर-1 टीस्पून, बेकिंग सोडा- 2 चुटकी विधि-

सबसे पहले सेब को धोकर छील लें और बीज निकालकर कद्दूकस कर लें। अब एक पैन में दूध को उबलें। उबल आने पर इसे चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक वह आथा न हो जाए। अब दूध में बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद दूध में चलाते हुए दूध के गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें चीनी और मेरे डालें और चलाते हुए 2-3 मिनट तक पका लें। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें और गैस बंद कर दें। इसे सर्विंग बाउल में निकालें और गरम या ठंडी सर्व करें।

### शब्द सामर्थ्य-64

बाएं से दाएं	15. वचन, जीभ 16. गोपियों को	मस्तक 6. कटोरी के आकार का नलीदार पात्र जिसमें तंबाकू रखकर पीते हैं 9. रेखा 10. खून से लथपथ 11. छिपक बुरी नजर से ताकने की क्रिया 12. व्यापार, धधा 13. शुंगर करना, सजन किवाड़ 14. श्रवणंदीय 15. सीमा, हट 16. चमड़ा, चाम 19. बोझ, आपसी व्यवहार का संबंध, वास्ता
1. संबंध, लगाव, नाता, काम 2. अगा की ज्वाला, सीलकर 4. फूलदार वृक्ष 5. प्रतिकार, प्रतिवाद 8. बाबूल की दुआएं लेती जा... 9. गीतवाली बलराज सहनी, मनोजकुमार, राजकुमार, वहानी 11. करताल ध्वनि 13. करताल ध्वनि 15. करताल की ऊंचाई को अंदर लगा छड़, चटखोनी 3. मास के अल्पतं छोटे दुकड़े 4. माथा,	स्वस्थ 4. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा, दरअसल, आम चुनाव से पहले यही तीक बक है जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलान किया जा सकता है।	
2. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा, दरअसल, आम चुनाव से पहले यही तीक बक है जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलान किया जा सकता है।	कर्मचारियों के लिए बड़े एलान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, बड़ी हुई सैलरी का फायदा जनवरी 2019 से मिलेगा, दरअसल, आम चुनाव से पहले यही तीक बक है जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलान किया जा सकता है।	
3. बाएं से दाएं	7. एक बैसिक पे 18000 रुपए से बढ़कर 21000 रुपए हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूतम वेतन 18 वर्जार रुपए करने की सिफारिश की थी। हालांकि, कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26 वर्जार रुपए करने की मांग कर रहे हैं।	रखेगी। इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी, जिसका असर उसके खाजाने पर पड़े। ज्यादा बोनस या सैलरी देने से सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है।
4. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा	26 जनवरी को एलान संभव के द्वारा लगाया जाएगा। आगमी चुनाव को देखते हुए बजट में कुछ घोषणा कब करेगी, इसे लंकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के बिर्यां के बोझों को अतिरिक्त तोहफा देकर सरकार बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार अपने वित्त उद्योगों के लिए बड़े एलान करने की अंतिम पूर्ण बजट को भी ध्यान में रखेगी।	रखेगी। इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी, जिसका असर उसके खाजाने पर पड़े। ज्यादा बोनस या सैलरी देने से सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है।
5. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा	26 जनवरी को एलान संभव के द्वारा लगाया जाएगा। आगमी चुनाव को देखते हुए बजट में कुछ घोषणा कब करेगी, इसे लंकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के बिर्यां के बोझों को अतिरिक्त तोहफा देकर सरकार बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार अपने वित्त उद्योगों के लिए बड़े एलान करने की अंतिरिक्त बोझ की बात सामने आई थी कि सरकार एरियर देने के मूड में नहीं है। वहां, सरकार के वित्तीय सलाहकारों ने वेतन वृद्धि से अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही थी।	रखेगी। इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी, जिसका असर उसके खाजाने पर पड़े। ज्यादा बोनस या सैलरी देने से सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है।
6. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा	26 जनवरी को एलान संभव के द्वारा लगाया जाएगा। आगमी चुनाव को देखते हुए बजट में कुछ घोषणा कब करेगी, इसे लंकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के बिर्यां के बोझों को अतिरिक्त तोहफा देकर सरकार बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार अपने वित्त उद्योगों के लिए बड़े एलान करने की अंतिरिक्त बोझ की बात सामने आई थी कि सरकार एरियर देने के मूड में नहीं है। वहां, सरकार के वित्तीय सलाहकारों ने वेतन वृद्धि से अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही थी।	रखेगी। इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी, जिसका असर उसके खाजाने पर पड़े। ज्यादा बोनस या सैलरी देने से सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है।
7. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा	26 जनवरी को एलान संभव के द्वारा लगाया जाएगा। आगमी चुनाव को देखते हुए बजट में कुछ घोषणा कब करेगी, इसे लंकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के बिर्यां के बोझों को अतिरिक्त तोहफा देकर सरकार बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार अपने वित्त उद्योगों के लिए बड़े एलान करने की अंतिरिक्त बोझ की बात सामने आई थी कि सरकार एरियर देने के मूड में नहीं है। वहां, सरकार के वित्तीय सलाहकारों ने वेतन वृद्धि से अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही थी।	रखेगी। इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी, जिसका असर उसके खाजाने पर पड़े। ज्यादा बोनस या सैलरी देने से सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है।
8. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा	26 जनवरी को एलान संभव के द्वारा लगाया जाएगा। आगमी चुनाव को देखते हुए बजट में कुछ घोषणा कब करेगी, इसे लंकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के बिर्यां के बोझों को अतिरिक्त तोहफा देकर सरकार बोझ बढ़ाने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार अपने वित्त उद्योगों के लिए बड़े एलान करने की अंतिरिक्त बोझ की बात सामने आई थी कि सरकार एरियर देने के मूड में नहीं है। वहां, सरकार के वित्तीय सलाहकारों ने वेतन वृद्धि से अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही थी।	रखेगी। इसलिए सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी, जिसका असर उसके खाजाने पर पड़े। ज्यादा बोनस या सैलरी देने से सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है।
9. संबंधित, सूलरी का फायदा 7. जनवरी 2019 से मिलेगा	26 जनवरी को एलान संभव के द्वारा लगाय	